राजस्व बढ़ाने और खर्च में कटौती करने के लिए उठाये गए कदम

532. **डा० रत्नाकर पाण्डेय:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय ने अपना राजस्व बढ़ाने और खर्च में कटौती करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितनी बचत किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) बचत की निश्चित मात्रा का आकलन नहीं किया जा सकता।

विवरण

राजस्व बढ़ाने और खर्च में कटौती करने के लिए उठाए गए कदम

रेलों पर यह सदैव प्रयास रहा है कि खर्च में कमी की जाये और आमदनी बढ़ायी जाये। खर्च कम करने के लिए अपनाये जा रहे कुछ विशिष्ट उपाय नीचे दिये गये हैं:—

1. अलाभप्रद शाखा लाईनों के कार्य संचालन की समीक्षा करना ताकि उन्हें अर्थक्षम बनाया जा सके।
2. फालतू कर्मचारियों को पुनः तैनात करने की योजनाओं सहित भाप शेडों और अन्य अनावश्यक गतिविधियों को बन्द करना।
3. ऊर्जा अर्थात् कोयले, डीजल और बिजली की खपत में बचत करना।
4. सड़क वाहनों की ईंधन की खपत पर अंकुश लगाना।
5. सामान्य प्रयोजनों के लिए भण्डार की मदों की खरीद की समीक्षा करना।
6. मात्रा और दरों की उपयुक्तता के विषय सन्दर्भ में स्थानीय खरीद और गैर-भण्डार की मदों की खरीद पर नियंत्रण रखना।
7. विज्ञापन, मनोरंजन आदि जैसी मदों पर होने वाले खर्च पर अंकुश लगाना।

आमदनी बढ़ाने तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गयी है:—

1. बेहतर विपणन प्रयास।
2. आमदनी की चोरी को रोकना।
3. वाणिज्यिक दोहन के जरिये और अतिक्रमण को हटाकर/रोक लगाकर रेलवे भूमि से राजस्व बढ़ाना।
4. वाणिज्यिक प्रचार बढ़ाना; और
5. रेलवे स्टेशनों पर निजी खान-पान यूनिटों और स्टालों से अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करना।

Clearance to Project for Coconut Plantation

533. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether any project report to cover one lakh hectare land under coconut plantation in the four districts of Trivandrum, Ernakulam, Trichur and Calicut for Rs. 12.37 crores, based on the guidelines under the Technology Mission on oilseeds, is pending before the Centre since 1987; and

(b) if so, whether Government propose to accord clearance for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) and (b) The Technology Mission on Oilseeds (TMO) had advised the State Governments to prepare State Mission documents for oilseeds development detailing therein the participating agencies, their precise role, objectives, targets etc., so that definite Operational Plan on a time bound basis could be implemented and closely monitored. On the basis of this advice, the Government of Kerala prepared a document indicating the Operational Plan and send a copy to TMO in July, 1987. In the Operational Plan, State Government had indicated a financial requirement of Rs. 21.38 crores for